

अपीलीय सिविल

मन मोहन सिंह गुजराल न्यायमूर्थ के समक्ष .

रंजीत कौर- अपीलकर्ता

बनाम

सुखदेव सिंह - प्रतिवादी।

1971 के आदेश संख्या 49-एम से पहली अपील।

9 नवंबर, 1971

हिंदू विवाह अधिनियम (1.955 का XXI) - धारा 13 (1 ए) और 23 (1) (ए) - पत्नी द्वारा प्राप्त न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री - डिक्री के दो साल के भीतर पति द्वारा सह-निवास करने से इनकार करना - क्या पति द्वारा अपनी गलती का लाभ उठाना - डिक्री के दो साल बीत जाने के बाद पति द्वारा तलाक के लिए याचिका - क्या सुनवाई योग्य है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 की उप-धारा (1 ए) के अवलोकन से पता चलता है कि तलाक का दावा करने का अधिकार विवाह के दोनों पक्षों को प्रदान किया गया है, न कि केवल उस पक्ष को जिसने न्यायिक अलगाव या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त की है। अधिनियम की धारा 23 में निस्संदेह यह प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा राहत प्रदान करने से पहले उसे इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि राहत देने का कोई भी आधार मौजूद है और इस धारा में उल्लिखित कोई भी सलाखों में राहत से इनकार करने के लिए मौजूद नहीं है। राहत से इनकार करने के आधारों में से एक याचिकाकर्ता द्वारा राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी गलती या विकलांगता का लाभ उठाना है। धारा 23 (1) द्वारा लगाई गई इस रोक को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि लिया गया लाभ उस आधार से संबंधित होना चाहिए जिस पर राहत का दावा किया गया है। किसी पार्टी को राहत देने से केवल तभी इनकार किया जा सकता है जब पार्टी द्वारा लाभ उठाया गया हो जब उस आधार पर राहत का दावा किया गया हो। जहां एक पत्नी न्यायिक अलगाव के लिए एक डिक्री प्राप्त करती है, डिक्री के दो साल के भीतर पति द्वारा पत्नी के साथ सह-निवास करने से इनकार करना इस निष्कर्ष को जन्म नहीं दे सकता है कि पति लाभ उठा रहा है।

रणजीत कौर बनाम सुखदेव सिंह (गुजरात, जे)

न्यायालय के हाथों राहत मांगते समय अपनी गलती या विकलांगता के बारे में इसलिए पत्नी द्वारा प्राप्त न्यायिक अलगाव की डिक्री के दो साल बीत जाने के बाद ऐसे पति द्वारा तलाक के लिए याचिका सुनवाई योग्य है (पैरा 7 और 11)

चंडीगढ़ के जिला न्यायाधीश श्री जोगिंदर सिंह मंदर की अदालत के दिनांक 1 मई 1971 के आदेश से पहली अपील याचिका को स्वीकार करते हुए और दोनों पक्षों के बीच तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद का आदेश दिया गया।

अपीलकर्ताओं के लिए रूप चंद, वकील।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एम. एल. सरिन, अधिवक्ता एच. एल. सरिन और अधिवक्ता एस. के. पिपत उपस्थित थे।

निर्णय

गुजरात, न्यायमूर्ति -(एक) यह चंडीगढ़ के जिला न्यायाधीश के 1 मार्च, 1970 के आदेश के खिलाफ अपील है, जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत सुखदेव सिंह, प्रतिवादी की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था और प्रतिवादी के पक्ष में तलाक द्वारा विवाह के विघटन के लिए एक डिक्री दी गई थी।

(दो) सितंबर 1966 में पार्टियों ने खुशी से शादी की, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी और शादी के कुछ समय बाद उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसके परिणामस्वरूप, दोनों पक्ष अलग-अलग रहने लगे और रणजीत कौर को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव के लिए याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया, और उसने 30 दिसंबर 1967 को न्यायिक अलगाव के लिए एक डिक्री प्राप्त की। यह एकतरफा आदेश था क्योंकि पति सुखदेव सिंह ने इसका विरोध नहीं किया था। दो साल बीत जाने के बाद सुखदेव सिंह ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें इस आधार पर तलाक का दावा किया गया कि न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री पारित होने के बाद दो साल से अधिक समय बीत चुका है और इस अवधि के दौरान पार्टियों ने सहवास फिर से शुरू नहीं किया है।

(तीन) अपीलकर्ता द्वारा याचिका का विरोध किया गया था और दो मुख्य आपत्तियां ली गई थीं। याचिका को बनाए रखने के लिए पति की लड़ाई को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता है, पति के आचरण के कारण पत्नी द्वारा न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री प्राप्त की गई है। दूसरी दलील यह थी कि एक समझौता किया गया है।

जनवरी 1969 में और लगभग पंद्रह दिनों के लिए सहवास फिर से शुरू करने वाले पक्षों के लिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी - पक्षकारों की दलीलों के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे: -

(एक) क्या याचिकाकर्ता एक साथ रहता है और प्रतिवादी के साथ सहवास करता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है?

(दो) क्या याचिका सुनवाई योग्य नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है?

दोनों मुद्दों को पत्नी के खिलाफ तय किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पति की याचिका को अनुमति दी गई थी, और प्रार्थना के अनुसार एक डिक्री दी गई थी।

(चार) अपीलकर्ता की ओर से मुद्दा संख्या 1 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया था- इस संबंध में मुख्य तर्क यह था कि पार्टियों ने जनवरी 1969 में लंबित आपराधिक कार्यवाही में समझौता किया था, यह निष्कर्ष निकालना उचित था कि पार्टियों ने सहवास फिर से शुरू कर दिया था। रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से यह पता चलता है कि सुखदेव सिंह के भाई हरभजन सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इसे 23 जनवरी 1969 को वापस ले लिया गया था। यह पता चला कि हरभजन सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 393 और 342 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसे भी वापस ले लिया गया था। इसके बाद हरभजन सिंह के पिस्टल लाइसेंस की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और एक आवेदन पर पति के रिश्तेदारों ने हस्ताक्षर भी किए थे- इन दस्तावेजों से यह सामने आया कि पक्ष उन आपराधिक मामलों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे जो उनके संबंधों के खिलाफ स्थापित किए गए थे। आपराधिक मुकदमेबाजी को समाप्त करने की इस इच्छा से यह जरूरी नहीं है कि पार्टियों ने एक साथ रहने का फैसला किया था।

(पाँच) अपीलकर्ता ने यह स्थापित करने के लिए मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व किया था कि उसके और उसके पति के बीच एक समझौता हो गया था और वे चंडीगढ़ में पंद्रह दिनों तक एक साथ रहे थे। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के सबूतों पर विस्तार से विचार किया था और उनकी गवाही पर अविश्वास करने के लिए बहुत ही ठोस कारण दिए हैं- अपीलकर्ता के विद्वान वकील विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा किए गए कारणों या निष्कर्षों को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं हैं। मेरी राय में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने बहुत ही प्रशंसनीय कारण दिए हैं, और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

रणजीत कौर *बनाम* सुखदेव सिंह (गुजराल, जे)

इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि वास्तव में कोई समझौता नहीं हुआ था और पार्टियां एक साथ नहीं रही थीं, ट्रायल कोर्ट इस तथ्य से भी प्रभावित था कि कथित समझौता केवल मौखिक था, और इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं लिखा गया था। यह देखते हुए कि सिविल और आपराधिक मुकदमेबाजी थी जिसमें न केवल पक्ष बल्कि उनके संबंध भी शामिल थे, अगर पार्टियों ने एक साथ रहने का फैसला किया था, तो कुछ दस्तावेज तैयार किए जाने थे, खासकर जब अपीलकर्ता ने न्यायिक अलगाव के लिए एक डिक्री प्राप्त की थी, जो किसी भी पक्ष द्वारा तलाक के लिए याचिका के लिए आधार प्रदान करने के लिए बाध्य था- विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण है, इसलिए, प्रशंसनीय है और इस निष्कर्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि पार्टियों ने जनवरी, 1969 में सहवास किया था।

(छः) अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि धारा 13 के तहत याचिका पति के कहने पर सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि उसने पत्नी को न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री प्राप्त करने के लिए मजबूर किया है और डिक्री का लाभ नहीं उठा सकता है। इस तर्क के लिए चमन लाई बनाम चमन लाई में दिए गए फैसले से समर्थन मांगा गया थामोहिंदर देवी (1)

(सात) 1964 के अधिनियम 44 में संशोधन करके हिंदू विवाह अधिनियम के संशोधन से पहले, जिस पक्ष के खिलाफ न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री प्राप्त की गई थी, वह इस आधार पर तलाक की मांग नहीं कर सकता था कि पार्टियों ने न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री पारित होने के बाद दो साल या उससे ऊपर की अवधि के लिए सहवास फिर से शुरू नहीं किया था। इसी तरह, संशोधन से पहले, जिस पक्ष के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त की गई थी, वह इस आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता था कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित होने के बाद दो साल की अवधि के लिए या उससे ऊपर की अवधि के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की बहाली नहीं हुई थी। संशोधित अधिनियम द्वारा धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (viii) और (ix) को हटा दिया गया और उपधारा (1A) अंतःस्थापित की गई जो निम्नलिखित शब्दों में है:-

(1ए) विवाह के लिए कोई भी पक्ष; चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में गंभीर हो, यह भी पेश कर सकता है

1971 पी.एल.आर. 104-आई.एल.आर. (1972) 2 Pb. & hr. 481.

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

1974(1)

आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए एक याचिका।

- (१) यह कि विवाह के पक्षकारों के बीच दो साल की अवधि के लिए या उससे ऊपर की अवधि के लिए सहवास की कोई बहाली नहीं हुई है, जिस कार्यवाही में वे पक्षकार थे; नहीं तो
- (२) यह कि विवाह के पक्षकारों के बीच वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दो साल की अवधि तक या उससे ऊपर की अवधि के लिए वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है, जिस कार्यवाही में वे पक्षकार थे।

उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि अब विवाह के दोनों पक्षों को एक अधिकार प्रदान किया गया है, न कि केवल उस पक्ष को जिसने न्यायिक अलगाव या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त की थी।

(आठ) चमानी लाई मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि आवश्यक अवधि के लिए वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक असंतुष्ट डिक्री का अस्तित्व अदालत के लिए तलाक के लिए डिक्री देने के लिए पर्याप्त था और उस मामले में धारा 23 (1) (ए) के प्रावधान लागू नहीं होते थे। यह तर्क नकारात्मक था और यह माना गया था कि धारा 13 की

उप-धारा (1 ए) धारा 23 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन थी क्योंकि बाद का प्रावधान एक अभिभावी प्रावधान की प्रकृति में था। धारा 28 (1) (ए) के दायरे को ध्यान में रखते हुए, चमन लाई के मामले में यह माना गया था कि आवश्यक अवधि के लिए वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक असंतुष्ट डिक्री का अस्तित्व तलाक के लिए डिक्री देने के लिए पर्याप्त नहीं था और धारा 13 की उप-धारा (1 ए) धारा 23 (1) के प्रावधानों के अधीन थी।

(नौ) उत्तरदाताओं की ओर से यह बताया गया है कि चमन लाई (1) के मामले में अपनाया गया दृष्टिकोण स्वीकार किया जाता है, यह 1964 के अधिनियम संख्या 44 द्वारा पेश किए गए संशोधन के प्रभाव को समाप्त कर देगा, विशेष रूप से धारा 13 (1 ए) के खंड (ii) द्वारा कवर किए गए मामलों में, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त की गई थी, वह इस डिक्री के आधार पर तलाक के लिए आवेदन करने में सक्षम नहीं होगा। यह तर्क दिया जाता है कि यदि उसने डिक्री का पालन करने और वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रयास किया

रणजीत कौर बनाम सुखदेव सिंह (गुजराल, जे)

ऐसा होने पर वह तलाक का हकदार नहीं होगा क्योंकि वह तलाक का दावा केवल तभी कर सकता है जब निर्धारित अवधि के भीतर वैवाहिक अधिकारों की बहाली नहीं होती है। दूसरी ओर, अगर वह डिक्री का पालन नहीं करता है, तो वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर राहत का दावा नहीं कर पाएगा। इसलिए, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि धारा 23 की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो उस उद्देश्य को विफल कर दे, जिसके लिए विधायिका ने उप-धारा (1 ए) की शुरुआत करके धारा 13 में संशोधन पेश किया था।

(दस) हालांकि उपरोक्त तर्क कुछ आकर्षक लगते हैं, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच करने पर उनमें कोई दम नहीं दिखता है। जैसा कि चमन लाल (1) में डिवीजन बेंच द्वारा बताया गया है, मामला "धारा 23 अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही को नियंत्रित करती है और यह स्पष्ट करती है कि जब तक उप-धारा (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है और अन्यथा नहीं होता है, तब तक अदालत उस राहत को नहीं देगी जिसके लिए प्रार्थना की गई थी"। इसके अलावा, चमन लाल (1) के मामले में निर्णय, इस न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय होने के नाते मेरे लिए बाध्यकारी है।

(ग्यारह) इस स्थिति का सामना करते हुए, श्री सरिन ने तर्क दिया कि जहां तक खंड (1) का संबंध है, धारा 13 की उप-धारा (1 ए) के खंड (ii) के तहत जो भी स्थिति रही हो, एक बार किसी भी पक्ष द्वारा न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री प्राप्त करने के बाद कोई भी पक्ष तलाक का दावा कर सकता है यदि दो साल के भीतर सहवास की बहाली नहीं हुई है। आगे तर्क यह है कि पत्नी द्वारा न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री प्राप्त करने के बाद पति द्वारा सहवास करने से इनकार करने से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि पति अदालत के हाथों राहत मांगते समय अपनी गलती या विकलांगता का लाभ उठा रहा था। सावधानीपूर्वक विचार करने पर तर्क अत्यधिक प्रशंसनीय प्रतीत होता है। धारा 23 में प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा राहत प्रदान करने से पहले यह संतुष्ट होना चाहिए कि राहत देने का कोई भी आधार मौजूद है और इस धारा में उल्लिखित कोई भी सलाखों का अस्तित्व राहत से इनकार करने के लिए मौजूद नहीं है। राहत देने से इनकार करने का एक आधार यह है कि क्या याचिकाकर्ता राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी गलती या विकलांगता का लाभ उठा रहा था। धारा 23 (1) द्वारा लगाई गई रोक को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि लिया गया लाभ उस आधार से संबंधित होना चाहिए जिस पर राहत का दावा किया गया है। अन्य में

शब्दों में, एक पार्टी को केवल तभी राहत देने से इनकार किया जा सकता है जहां पार्टी द्वारा लाभ उठाया गया हो, जिसके आधार पर राहत का दावा किया गया है। यह सिद्धांत *चमन लाई (1)* के मामले में निर्णय के अनुपात से भी उभरता है। उस मामले में, पार्टी वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री का लाभ उठाना चाहती थी, जिसने डिक्री का पालन करने से इनकार करके दूसरे पक्ष के साथ गलत किया था। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त होने के बाद जो गलत किया गया था, उसे *चमन लाई* के मामले (1) में सही माना गया था, कि धारा 23 (1) द्वारा लगाई गई रोक लागू होगी। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने न्यायिक अलगाव के लिए एक पक्षीय डिक्री प्राप्त की थी। उसके बाद वह डिक्री प्राप्त की गई थी जिसके आधार पर अब तलाक द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री की मांग की जा रही थी। प्रतिवादी ने इस तरह से काम नहीं किया था जो इस निष्कर्ष को जन्म दे सके कि वह अपनी गलती का फायदा उठा रहा था। इस स्तर पर यह विचार करना प्रासंगिक नहीं होगा कि पत्नी किस आधार पर न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री प्राप्त करने में सक्षम थी क्योंकि एकमात्र प्रासंगिक विचार न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री का अस्तित्व और न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री की अनुपस्थिति और दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए पार्टियों के बीच सहवास की अनुपस्थिति है। प्रतिवादी को राहत देने से केवल तभी इनकार किया जा सकता है जब न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री पारित होने के बाद उसने कुछ गलत किया हो और गलत का ऐसा लाभ उठाया हो जिसके बिना वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1 ए) (आई) के तहत तलाक द्वारा विवाह के विघटन के लिए डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई जगह नहीं है कि तलाक द्वारा विवाह के विघटन के लिए डिक्री पर प्रतिवादी का दावा उसके द्वारा किए गए कुछ गलत कार्यों पर आधारित है। मेरी राय में, इसलिए, धारा 23 (1) (ए) प्रतिवादी को राहत मिलने के रास्ते में नहीं आती है।

(बारह) मेरे समक्ष किसी अन्य मुद्दे पर जोर नहीं दिया गया है। अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। हालांकि, पार्टियों को अपनी लागत को वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अमृतबीर कौर

प्रक्षिप्त न्यायिक अधिकारी

अससंध, कर्नल
हरियाणा

